RBI क्यों और कैसे सरकार को वित्त हस्तांतरित करता है

लेखक- शाजी विक्रमण (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

28 अगस्त, 2019

"बैंकों के केंद्रीय बोर्ड ने 1.76 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड हस्तांतरण का फैसला किया है। ऐसे हस्तांतरण किस आधार पर किए जाते हैं? यह कभी-कभी विवादों में क्यों घिर जाता है और इस बार की राशि कैसे तय की गई है? इन्हीं सब सवालों का उत्तर हम इस आलेख में जानेंगे।"

सोमवार को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष - 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

अधिशेष या मुनाफे के हस्तांतरण का मुद्दा अक्सर विवादास्पद रहा है। सरकार अक्सर आरबीआई से ज्यादा से ज्यादा भुगतान करने की मांग करती है, जिसके लिए वह यह तर्क देती है कि उसे वादों को पूरा करने और आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है, जबकि एक परंपरागत केंद्रीय बैंक, मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ एक अच्छा हिस्सा अपने पास बुरे दिनों के लिए रखना पसंद करता है। शायद ही कभी यह लड़ाई उतनी कड़वी रही होगी जितनी पिछले साल थी, जब उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर थे और सुभाष गर्ग वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे। इस बार बहस यह थी कि आरबीआई किस हद तक भंडार को अपने पास रखेगा और किस स्तर तक सरकार को वापस देगा। हालांकि, इस मुद्दे को सोमवार को सुलझा लिया गया।

आरबीआई हर साल अपने अधिशेष को सरकार को हस्तांतरित करता है, तो इस बार किया गया भुगतान क्यों इतना खास है?

हाँ, आकस्मिक या संभावित नुकसान के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के बाद, RBI अपने अधिशेष को सरकार, जो इस संस्था की मालिक है, को प्रतिवर्ष हस्तांतरित करता है। वितरित किया गया लाभ पिछले कुछ वर्षों में विविध रहा है, औसतन 50,000 करोड़ रुपये से अधिक।

आरबीआई बोर्ड ने सोमवार को पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अतिरिक्त पूंजी के हस्तांतरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्रीय बोर्ड ने 1.23 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष और वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के 52,637 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का फैसला किया है। यह पहली बार है कि जब आरबीआई इतनी बड़ी राशि, एकमुश्त हस्तांतरण का भुगतान करेगा। इससे पहले, सरकार ने बजट में रिवर्ज बैंक के लिए 90,000 करोड़ रुपये का लांभाश प्रस्तावि किया था।

किस औचित्य पर इतना बड़ा भुगतान मंजूर किया गया?

आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अधिशेष या मुनाफे का स्तर लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। पिछले एक दशक या उससे अधिक समय से, सरकार ने उच्च भुगतान की मांग करते हुए कहा था कि आरबीआई के पास इतना आरक्षित या पूंजीगत भंडार है जितना कई अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास भी नहीं है। सरकार ने तर्क दिया है कि इस तरह के अपेक्षाकृत कम हस्तांतरण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक खर्च को संकुचित कर देगा और साथ ही इससे घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में दिक्कतें आएंगी। सरकार द्वारा उच्च अंतरण की अपनी मांग को बढ़ाने के साथ, जालान

समिति ने आरबीआई बैलेंस शीट से संबंधित पूंजी संरचना, वैधानिक प्रावधानों और अन्य मुद्दों की समीक्षा की है। आरबीआई की पूंजी संरचना पर विशेष रूप से असंगठित लाभ (जो अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं किए गए हैं) की समीक्षा करने के बाद और वित्तीय स्थिरता, संभावित जोखिम और वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, समिति ने 1.76 लाख करोड़ रूपए के कुल हस्तांतरण का सुझाव दिया।

आरबीआई कैसे अधिशेष उत्पन्न करता है?

आरबीआई की कमाई का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय बाजारों में RBI के इन संचालनों से आता है:- जब यह विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए हस्तक्षेप करता है; ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जब यह रुपये को बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है; सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय से; अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से रिटर्न के रूप में जो विदेशी केंद्रीय बैंकों या टॉप रेटेड प्रतिभूतियों के बॉन्ड में निवेश करता है; अन्य केंद्रीय बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय निपटान या बैंक के लिए जमा राशि से आता है; राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के उधार को संभालने के लिए बहुत कम कार्यकाल और प्रबंधन आयोग के लिए बैंकों को ऋण देने से आता है। RBI इन वित्तीय परिसंपत्तियों को अपनी निश्चित देनदारियों के खिलाफ खरीदता है, जैसे कि जनता द्वारा अपने पास रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों को जारी की गई जमाएँ, जिन पर वह ब्याज का भुगतान नहीं करता है।

आरबीआई का व्यय मुख्य रूप से नोटों की छपाई पर, कर्मचारियों पर, इसके अलावा, सरकार की ओर से और प्राथमिक डीलरों से लेन-देन करने के लिए बैंकों को दिए गये कमीशन पर होता है। केंद्रीय बैंक की कुल लागत, जिसमें मुद्रण और कमीशन रूपों पर व्यय शामिल है, इसकी कुल शुद्ध ब्याज आय का केवल 1/7वां हिस्सा है।

लाभांश के बजाय इन्हें सरकार को स्थानान्तरण क्यों कहा जाता है?

ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है, जैसे-बैंक और अन्य कंपनियां, जिस पर स्वामित्व या नियंत्रण सरकार का होता है और ये उत्पन्न लाभ से लाभांश का भुगतान करते हैं। यद्यपि इसे 1935 में निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में 5 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, सरकार ने इसे जनवरी 1949 में 'मालिक' बना दिया। आरबीआई अधिशेष, जो व्यय से अधिक आय होता है, सरकार को हस्तांतरित कर देता है। RBI अधिनियम की धारा-47 के तहत, "बैड लोन के लिए प्रावधान करने के बाद, परिसंपत्तियों में मूल्य ह्रास, कर्मचारियों और सुपरनेशन/प्रोविडेंट फंड में योगदान और अन्य सभी मामलों, जिसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं, उसके बाद केंद्रीय बैंक अपनी अधिशेष राशि सरकार को भुगतान करेगा और इसे प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बोर्ड द्वारा अगस्त की शुरुआत में किया जाता है।

विश्व स्तर पर, केंद्रीय बैंकों द्वारा लाभांश के भुगतान से संबंधित नियम क्या हैं?

कई शीर्ष केंद्रीय बैंकों-यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जर्मन बुंडेसबैंक, बैंक ऑफ जापान में कानून यह स्पष्ट करते हैं कि मुनाफे को सरकार या ट्रेजरी में स्थानांतरित किया जाना है। वितरित किए जाने वाले मुनाफे या प्रतिशत की मात्रा भी कानूनों में निर्दिष्ट है।

तो, भारत में अब और पहले की तुलना में क्या भिन्नताएं आई हैं?

कितना हस्तांतरित करना है, इस पर सरकार और आरबीआई के बीच चर्चा की जाती है और फिर निर्णय लिया जाता है। समय-समय पर, इसे आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है। विदित हो कि पिछली बार जब वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता वाली समिति ने रघुराम राजन के समय में किए गए मुनाफे का 100% वितरित करने की सिफारिश की थी। अब अंतर यह है कि जालान समिति की लाभ वितरण नीति पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा समर्थन किया गया है। इसका मतलब अगले साल से कई अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह ही पारदर्शी और नियम आधारित भुगतान होगा, जो सरकार और आरबीआई के बीच संकीर्ण मतभेदों को दूर करने में मदद् कर सकता है।

इस बड़े अधिशेष के साथ सरकार क्या करेगी?

आम तौर पर, पैसा भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ से सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाता है और सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च करने के अलावा ब्याज भुगतान किया जाता है। बड़े भुगतान से सरकार को नियोजित उधार पर कटौती करने और ब्याज दरों को अपेक्षाकृत कम रखने में मदद् मिल सकती है। इसके अलावा, यह निजी

कंपनियों को बाजारों से पैसा जुटाने के लिए जगह प्रदान करेगा और अगर यह अपने राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का प्रबंधन करता है, तो इस अप्रत्याशित लाभ से वित्तीय घाटा कम हो सकता है। दूसरा विकल्प इन फंडों को सार्वजनिक खर्च या विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित करना है, जिससे कुछ क्षेत्रों में मांग में सुधार हो सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

उच्च भुगतान से संबंधित संभावित मुद्दे क्या हैं?

इस प्रश्न को पूर्व गवर्नर राजन द्वारा व्यक्त किया गया है। उनके अनुसार, आरबीआई के अधिशेष का अधिकांश हिस्सा सरकारी परिसंपत्तियों (प्रतिभूतियों या बॉन्ड) पर ब्याज या अन्य बाजार सहभागियों से किए गए पूंजीगत लाभ से आता है। उन्होंने आगे कहा कि जब यह सरकार को भुगतान करता है, तो आरबीआई उसी सिस्टम में पुन: पैसे को वापस डाल देता, जहाँ से इसने पैसा कमाया था; इसमें कोई अतिरिक्त पैसे की छपाई या रिजर्व निर्माण शामिल नहीं है। लेकिन जब आरबीआई अतिरिक्त लाभांश का भुगतान करता है, तो उसे अतिरिक्त स्थायी भंडार या बोलचाल की भाषा में बोले तो पैसा प्रिंट करने पड़ते हैं। इसलिए, विशेष लाभांश को समायोजित करने के लिए, आरबीआई को अपने पोर्टफोलियो में सरकारी बॉन्ड बेचकर जनता से बराबर धन वापस लेना होगा।

केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में हस्तांतरण करने से क्यों कतराता है?

विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जब केंद्रीय बैंकों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अपरंपरागत साधनों का सहारा लेना पड़ा, तो भविष्य के जोखिम या नुकसान के खिलाफ संभावित बीमा के रूप में उच्च पूंजी, भंडार और अन्य निधियों के रूप में पर्याप्त बफर्स का निर्माण किया गया है। एक संकट के दौरान एक उच्च बफर केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और नई पूंजी के लिए सरकार पर आश्रित होने से बचाता है और इस तरह वित्तीय स्वायत्तता कायम रहती है।

अतीत में इस मुद्दे पर व्याप्त विवाद को देखते हुए, इस बार मुनाफे का वितरण कैसे तय हुआ?

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने अपने संस्मरण में लिखा था कि इस पर साल-दर-साल बहस होती रहेगी लेकिन अगर दोनों पक्ष इस मुद्दे पर कुछ लचीलापन दिखाते हैं, तो एक बेहतर समझौता संभव हो सकेगा।

GS World टीम...

आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बोर्ड ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- इसका बड़ा हिस्सा (1.23 लाख करोड़ रुपये) सालाना सरप्लस है, जबकि बाकी (52,637 करोड़ रुपये) रकम सरप्लस रिजर्व की है।
- इससे सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाये बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद् मिलेगी।
- अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि आरबीआई की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों (ईसीएफ) के आधार पर निकाली गयी है।
- विदित हो कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है। छह सदस्यीय जालान समिति को 26 दिसंबर, 2018 को नियुक्त किया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का रिजर्व, आदर्श रूप में कितना होना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए इससे पहले तीन समितियां बन चुकी हैं। साल 1997 में वी.सुब्रह्मण्यम, साल 2004 में ऊषा थोराट और साल 2013 में वाई.एच. मालेगाम की अगुआई वाली समिति बनाई गई थी।
- आरबीआई ने 2014 में सरकार को 52679 हजार करोड़ का, 2015 में 65896 हजार करोड़ का, 2016 में 65876 हजार करोड़ का, 2017 में 30659 हजार करोड़ का, 2018 में 50000 हजार करोड़ का सरप्लस दिया था। 2019 में यह रकम बढ़कर 1.76 लाख करोड़ हो गई है।

आरबीआई की बैलेंस शीट कितनी बड़ी है?

- वित्त वर्ष 2017-18 में आरबीआई की बैलेंस शीट 36.2 लाख करोड़ रुपये की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट जैसी नहीं है।
- आरबीआई जो नोट छापता है उसकी केंद्रीय बैंक की लाइबिलिटी में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी होती है। 26 फीसदी हिस्सेदारी उसके रिजर्व की होती है।
- इनका निवेश विदेशी और देशी सिक्योरिटीज के साथ ही सोने में किया जाता है।
- आरबीआई के पास 566 टन से थोड़ा ज्यादा सोना है। केंद्रीय बैंक के कुल एसेट में सोना और विदेशी मुद्रा की हिस्सेदारी करीब 77 फीसदी है।
- कभी-कभी इस बात को लेकर आरबीआई और सरकार के बीच में मतभेद पैदा होता है कि कामकाज जारी रखने के लिए आरबीआई के पास कितना रिजर्व होना चाहिए।

कहाँ से आता है आरबीआई का रिजर्व?

- यह समझने के लिए कि स्थानांतरण क्या है, हमें पहले यह समझना चाहिए कि धन कहाँ से आता है। केंद्रीय बैंक के पास तीन अलग-अलग फंड हैं, जो एक साथ अपने भंडार को शामिल करते हैं। ये मुद्रा और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट (CGRA), आकस्मिकता निधि (CF) और एसेट डेवलपमेंट फंड (ADF) हैं।
- आरबीआई का पूरा रिजर्व एक तरह का नहीं होता है। दो तरह के रिजर्व सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये हैं-करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट (CGRA)।
- रिजर्व में इनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। 2017-18 में यह 6.91 लाख करोड़ रुपये था। इस रिजर्व का मतलब सोना और विदेशी मुद्रा से है। केंद्रीय बैंक भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह रिजर्व रखता है।
- आसान शब्दों में कहें, तो इन एसेट्स के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ इस रिजर्व की वैल्यू घटती-बढ़ती रहती है।
- इस तरह बाजार की स्थितियों के मुताबिक केंद्रीय बैंक को रिजर्व के मामले में फायदा और नुकसान होता रहता है।
- उदाहरण के लिए, सीजीआरए 2010 के 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से काफी बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और सोने के भाव में उछाल इसकी वजह थी।
- 2017-18 में 2.32 लाख करोड़ की राशि के बाद सीएफ दूसरा सबसे बड़ा फंड है। यह विनिमय दर संचालन और मौद्रिक नीति निर्णयों से आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह आरबीआई के मुनाफे से बड़े हिस्से में वित्त पोषित है।

जालान समिति ने क्या सिफारिश की थी?

- जालान समिति, जैसा कि अनौपचारिक रूप से कहा गया था, वास्तव में RBI की एक्स्टेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति कहलाती है।
- समिति ने सिफारिश की कि RBI केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के 5.5-6.5% के बीच आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखता है।
- चूंकि नवीनतम सीएफ राशि आरबीआई की बैलेंस शीट का लगभग 6.8% थी, इसलिए अतिरिक्त राशि सरकार को हस्तांतरित की जानी थी।
- समिति ने अनुशंसित सीमा के 5.5% की निचली सीमा का उपयोग करने का भी निर्णय लिया है। इसलिए, मूल रूप से, CF में RBI की संपत्ति का 5.5% से अधिक जो भी था, उसे हस्तांतरित किया जाना था। वह राशि 52,637 करोड़ थी।
- RBI के आर्थिक पूंजी स्तरों के बारे में - जो अनिवार्य रूप से CGRA है - समिति ने उन्हें बैलेंस शीट के 20-24.5% के दायरे में रखने की सिफारिश की है। चूंकि यह जून, 2019 तक 23.3% था, इसलिए समिति को लगा कि इसमें और अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए RBI की पूर्ण शुद्ध आय- 1,23,414 करोड़ - केंद्र को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिशेष के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

   1. वाई.एच. मालेगाम समिति ने आर.बी.आई. के अधिशेष को सौ फीसदी सरकार को वितरित करने के लिए सिफारिश की थी।
   2. आर.बी.आई. का यह अधिशेष लाभांश के रूप में सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements, in the context of surplus of Reserve Bank of India-**

   1. Y.H. Malegam committee recommended to distribute 100% of the surplus of RBI to the government.
   2. This surplus of RBI is transferred to the government in the form of dividend.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1

   (b) Only 2

   (c) Both 1 and 2

   (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिशेष से आप क्या समझते हैं? इस अधिशेष को आर.बी.आई. लाभांश के रूप में न रखकर केन्द्र सरकार को हस्तांतरित कर देती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

Q. What do you understand by the surplus of Reserve Bank of India? This surplus is transferred to the Central Government by RBI instead, of keeping it as an dividend, why? Explain. (250Words)

नोट : 27 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

Committed